



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)  
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 262]  
No. 262]

नई दिल्ली, सोमवार, जून 30 1986/आशा 9 1908  
NEW DELHI, MONDAY, JUNE 30, 1986/ASADHA 9, 1908

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती हैं जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में  
रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a  
a separate compilation

## उद्योग मंत्रालय

(औद्योगिक विकास विभाग)

आदेश

नई दिल्ली, 30 जून, 1986

का. आ. 390(अ) —केन्द्रीय सरकार ने भारत सरकार के उद्योग और नागरिक प्रति मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग) के आदेश सं. का. आ. 422 (अ), तारीख 5 अगस्त, 1975 द्वारा (जिसे इससे इसके पश्चात् उक्त आदेश कहा गया है), उसमें विनिर्दिष्ट व्यक्तियों के निकाय को मैसर्स एंजिल इंडिया मशीन टूल्स लिमिटेड कलकत्ता नामे औद्योगिक उपक्रम का (जिसे इसके पश्चात् उक्त औद्योगिक उपक्रम कहा गया है) प्रबंध 5 अगस्त, 1975 से 5 (पांच) वर्ष की अवधि के लिए ग्रहण करने के लिए प्राधिकृत किया था,

और केन्द्रीय सरकार के उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग) ने अपने आदेश सं. का. आ. 292 (अ), तारीख 16 मई, 1979 द्वारा सचिव, वन्द और रुग्ण उद्योग विभाग, पश्चिमोत्तरांचल जलपरकार को जिसे अब सचिव, औद्योगिक पुर्नविभाग विभाग, पश्चिमोत्तरांचल

सरकार कहा जाता है (जिसे इसमें इसके पश्चात् प्राधिकृत व्यक्ति कहा गया है), पूर्वोक्त व्यक्तियों के निकाय से औद्योगिक उपक्रम का प्रबंध 5 अगस्त, 1975 से पांच वर्ष की अवधि के लिए ग्रहण करने के लिए प्राधिकृत किया था ;

और, केन्द्रीय सरकार ने, अपनी यह राय होने पर कि लोकहित में यह समीचीन है कि उक्त आदेश पूर्वोक्त पांच वर्ष की अवधि के प्रभाव के पश्चात् प्रभावी बना रहे, 30 जून, 1986 तक की, जिसमें यह तारीख भी सम्मिलित है, और अवधि के लिए ऐसे प्रबंधों को रद्द करने के लिए समय पर निर्देश जारी किए थे। देखिए भारत सरकार, उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग) के आदेश सं. का. आ. 603(अ), तारीख 1 अगस्त, 1980, सं. का. आ. 20 (अ), तारीख 3 अगस्त, 1981, सं. का. आ. 554 (अ), तारीख 4 अगस्त, 1982, का. आ. 87 (अ), तारीख 4 फरवरी, 1983, का. आ. 552 (अ)/18 चक्र/आई. डी. आर. ए./83, तारीख 4 अगस्त, 1983, का. आ. 408 (अ)/18 चक्र/आई. डी. आर. ए./84 तारीख 28 मई, 1984, का. आ. 968(अ)/18 चक्र/आई. डी. आर. ए./84, तारीख 28-12-84 और का. आ. 490 (अ) तारीख 27 जून, 1985,

और केन्द्रीय सरकार ने, अपनी यह राय होने पर कि लोकहित में यह समीचीन है कि औद्योगिक उपक्रम का प्रबन्ध प्राधिकृत व्यक्ति के पास 30 जून, 1987 तक की, जिसमें यह तारीख भी सम्मिलित है, और अवधि के लिए बना रहे, उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 (1951 का 65) की धारा 18 बक की उपधारा (2) के परन्तुक के अधीन उन आशय को अनुज्ञा के लिए निवेदन करते हुए, कलकत्ता उच्च न्यायालय को एक आवेदन किया था और उक्त उच्च न्यायालय ने तारीख 19 जून, 1986 के अपने आदेश द्वारा उक्त अनुज्ञा दी है ;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 (1951 का 65) की धारा 18 बक की उपधारा (2) के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियाँ का प्रयोग करते हुए निदेश देती है कि उक्त आदेश 30 जून, 1987 तक को, जिसमें यह तारीख भी सम्मिलित है, और अवधि के लिए प्रभाव बना रहेगा ।

[फा. नं. 2(17)/80-सो. सू. एव.]

ए. वी. गोकक, संयुक्त सचिव

## MINISTRY OF INDUSTRY

(Department of Industrial Development)

### ORDER

New Delhi, the 30th June, 1986

S.O. 390(E).—Whereas by the Order of the Government of India in the Ministry of Industry and Civil Supplies (Department of Industrial Development) No. S.O. 422(E), dated the 5th August, 1975 (hereinafter referred to as the said Order), the Central Government authorised the body of persons specified in that Order to take over management of the Industrial Undertaking known as the Messrs Engel India Machine and Tools Limited, Calcutta (hereinafter referred to as said industrial undertaking) for a period of 5 years from the 5th August 1975;

And, whereas, the Central Government in the Ministry of Industry (Department of Industrial Development) in its Order No. S.O. 292(E), dated the 16th May, 1979, authorised the Secretary, Closed and Sick Industries Department of the Government of West Bengal, now called Secretary, Industrial Reconstruction Department, Government of

West Bengal (hereinafter referred to as the authorised person) to takeover the management of the said industrial undertaking from the aforesaid body of persons for the remaining period of five years from the 5th August, 1975;

And, whereas, the Central Government being of opinion that it is expedient in the public interest that the said Order should continue to have effect after the expiry of the period of five years aforesaid, had issued directions from time to time, for such continuance for a further period upto and inclusive of the 30th June, 1986 (vide Orders of Government of India in the Ministry of Industry (Department of Industrial Development) Nos. S.O. 603(E), dated the 1st August, 1980, S.O. 620(E), dated the 3rd August, 1981, S.O. 554(E), dated the 4th August, 1982, S.O. 87(E), dated the 4th February, 1983, S.O. 552(E) 18FA/IDRA/83, dated the 4th August 1983, S.O. 408(E) 18FA/IDRA/84, dated 29th May, 1984, S.O. 968(E) 18FA/IDRA/84, dated the 28th December, 1984 and S.O. 490(E), dated the 27th June, 1985;

And, whereas, the Central Government, being of the opinion that it is expedient in the public interest that the authorised person should continue to manage the said industrial undertaking for a further period upto and inclusive of 30th June, 1987, make an application to the Calcutta High Court praying for permission to that effect under the proviso to sub-section (2) of section 18FA of the Industries (Development & Regulation) Act, 1951 (65 of 1951), and that the said High Court has, by its Order dated the 19th June, 1986, granted the said permission;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by the proviso to sub-section (2) of section 18FA of the Industries (Development & Regulation) Act, 1951 (65 of 1951), the Central Government hereby directs that the said Order shall continue to have effect for a further period upto and inclusive of 30th June, 1987.

[F. No. (17)/80-Cus.]

(A. V. GOKAK), Jt. Secy.